

# उद्यमों को विकसित करने 'प्रोजेक्ट हैंडमेड इन इंडिया' होगा लागू : डॉ. सुनील

सच प्रतिनिधि || भोपाल

ईडीआईआई पिछले 5 वर्षों से स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के लिए मध्यप्रदेश में एमपीएसआरएलएम के साथ काम कर रहा है। ईडीआईआई द्वारा मध्यप्रदेश में आवंटित चार ब्लॉकों में 7,500 से अधिक आजीविका उद्यमों को बढ़ावा दिया है। जिनमें आदिवासी और महिला उदमियों की बहुलता है।

इसी दिशा में ईडीआईआई ने मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थानों जैसे मध्य प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर और राज्य सरकार के साथ कई अन्य एमओयू (समझौता ज्ञापन) किया है। राज्य में प्रमुख शिक्षा संस्थानों के सहयोग से ईडीआईआई का इरादा फिनटेक, एडुटेक, क्लीनटेक, हेल्थटेक, बायोटेक, आदि जैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्र उद्यमिता के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है।

यह बात ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ल ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने और विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से उद्यमों को

विकसित करने के लिए महेश्वर में 'प्रोजेक्ट हैंडमेड इन इंडिया' लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश मैंगनीज, तांबा, कांच, चूना पत्थर, आदि में प्रमुख उत्पादन के साथ भारत में खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक प्रदेश है, और हीरे के भंडार के बाला भारत का एकमात्र राज्य है। इसमें भारत के कुल कोयला भंडार का 8 प्रतिशत से अधिक और 1,434 बिलियन क्यूबिक मीटर कोल-बेड मीथेन है। मध्य प्रदेश में देश के सभी 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश सोयाबीन, दालें, चना, लहसुन, गेहूं, मक्का और हरी मटर के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश केला, संतरा, अमरूद, आम और नींबू फल उगाने में भी अग्रणी है। भारत की कुल जैविक खेती में राज्य का योगदान 40 प्रतिशत से अधिक है।

श्री शुक्ल ने बताया कि ईडीआईआई मध्य प्रदेश में एमपी एसआरएलएम के साथ मिलकर ग्रामीण उद्यमिता के विकास के लिए एसवीईपी परियोजना के तहत डिंडोरी, बड़वानी, श्योपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में स्टार्ट अप विलेज कार्यक्रम लागू कर रहा है। ईडीआईआई पहले ही मप्र में 7,500 से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा दे चुका है।